

बिहार की कानून व्यवस्था और 243 सीटों को लेकर चिराग पासवान के बोल– सिर्फ बयान या भविष्य की राजनीति का संकेत ?

बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव से लेकर विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता को लालू यादव-राबड़ी देवी के जंगलराज की लगातार याद दिला रहे जेडीयू और भाजपा के नेता सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बयान ने एनडीए गठबंधन में खासकर जेडीयू नेताओं में खलबली मचा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजधानी पटना के पोंश इलाके में एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर अपनी ही गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने बहुत ही तल्ख अंदाज में इस हत्या को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह हत्याकांड इस बात का संकेत है कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चिराग की पार्टी ने उनके बयान के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। चिराग ने नीतीश सरकार पर सीधा-सीधा हमला बोलते हुए कहा, ‘जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है और कानून-व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, यह चिंता का विषय है। मैं केवल किंग व्यापारी की हत्या को लेकर नहीं कह रहा हूं,हालांकि यह भी नित्ता का विषय है क्योंकि ऐसी जगह पर यह घटना घटी है जो पटना का एक पोंश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर जहां थाना है और अधिकारियों के घर हैं। यदि यहां पर ऐसी घटना घट रही है तो सीचिए गांव-देहात में क्या हो रहा होगा ? अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिे चिंता का विषय होना चाहिए। कहां चूक हुई है, इसे हमें सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमें एक उदाहरण देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे।’ चिराग पासवान का यह बयान विपक्षी नेताओं के बयानों को और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आता है कि लालू-राबड़ी के जंगलराज की बात करने वाले नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं,अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सुशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बयान के मायने क्या है ? वह चाहते क्या हैं ? यह कोई पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने अपने बयान से बिहार की नीतीश सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा की हो। इससे पहले भी वो लगातार कई मौकों पर बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बना चुके हैं। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर रखी है। एक तरफ वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में शामिल होते हैं, लगातार एनडीए गठबंधन को चुनाव में विजयी बनाने की बात करते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं होने की बात कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। चिराग पासवान के विरोधाभासी बयानों ने बिहार की राजनीति को उलझा दिया है। जरा उनके और उनके बहनोई एवं लोकसभा सांसद अरुण भारती के कुछ बयानों पर नजर डालिए। एक तरफ जहां चिराग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है तो दूसरी तरफ वह खुद विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं वह बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार जाने की बात कर रहे हैं। छपरा में एक बार फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को दोहराते हुए कहा कि, ‘आज साराण की इस पावन धरती से, आप सबके सामने मैं यह कहकर जा रहा हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करूंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो सही मायनों में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएगा।’ इससे पहले उनके बहनोई एवं लोकसभा सांसद अरुण भारती एक वीडियो जारी कर चिराग पासवान के शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। अरुण भारती को चिराग पासवान ने पार्टी का चीफ व्हिप भी बनाया हुआ है और वह लगातार यह भी बयान दे रहे हैं कि बिहार चिराग पासवान को बुला रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान को बुला रहा है (बकौल लोजपा नेता) तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे ? और अगर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है (जैसा कि चिराग पासवान ने स्वयं कई बार कहा है) तो क्या वह केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री का पद और सांसदी सिर्फ एक विधायक बनने के लिए छोड़ेंगे ? उनकी पार्टी को एनडीए गठबंधन में किसी भी सूत में 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है, यह जानने के बावजूद एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं।

अजब-गजब

बेटे के दोस्त से इश्क कर बैठी 50 साल की महिला, हुई प्रेग्नेंट और कर ली शादी !



कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी क्या अंधा कि कोई अपने बेटे के दोस्त से ही बेवनाह इश्क कर बैठे। पड़ोसी मुल्क चीन से एक ऐसी ही ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। यहां एक 50 वर्षीय महिला को अपने बेटे के रूसी दोस्त से प्यार हो गया। इतना ही नहीं, महिला प्रेनेंट भी हो गई, और दोनों ने शादी भी रचा ली है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, चीन के गुआंगझोउ की रहने वाली 50 वर्षीय बिजनेसवमन सिस्टर शिन डॉयिन (चीनी टिकटॉक) पर अपने रूसी पति डेफू के साथ डेली लाइफ की तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं, जो कभी 30 साल की उम्र में तलाकशुदा थीं। शिन ने अकेले ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश की। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिन का पति और कोई नहीं, बल्कि उनके ही बेटे का दोस्त है। अब आइए जानते हैं कि कैसे हुई थी इनकी मुलाकात, और दोनों कब एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए।

बात छह साल पहले की है, जब चाइनीज न्यू इंपर के मौके पर शिन के बेटे कार्डिकाई ने अपने नतीन विदेशी दोस्तों को डिनर पर बुलाया, जिनमें डेफू भी एक था। यह रूसी छात्र फरिटदार चीनी बोलता था, और शिन के बेटे से कुछ साल सनिययर था। डेफू को शिन के हाथ का बना खाना इतना पसंद आया कि एक हफ्ते तक उनके ही घर में रुका रहा। ये भी देखें: Viral Video: तूफान में मछली पकड़ते शस्त्र पर दो बार हिराे बिजली, फिर भी बाल-बाल बचा !

शिन ने बताया कि तब वह और भी जवां और आकर्षक थीं। घर से जाने के बाद भी डेफू उनके संपर्क में रहा, और सली गिफ्ट्स और सरप्राज ब्रेकता रहा। उन्होंने कहा, एक दिन उसने मुझे अचानक प्रपोज कर दिया। यह जानकर मैं दंग रह गई। हालांकि, दोनों की उम्र में 20 साल का फासला और डेफू का लंबा कद शिन को उसके करीब आने से रोकते रहे। ये भी देखें: बिरयानी के साथ महिला ने किया ऐसा प्रयोग, लोग बोले- ये तो अल्टाचार है! लेकिन कहते हैं न इश्क में दूबे इसनों को कौन रोक पाया है। मजे की बात तो यह है कि बेटे के कहने पर ही शिन ने डेफू के प्यार को स्वीकार किया। दोनों ने शादी भी रचा ली है, और अब पूरे चीन की यात्रा पर हैं, जहां वे खुब रोमांटिक पल बिता रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ, जब 8 जून को 50 वर्षीय इस महिला ने अपने फॉलोवर्स को खुद के प्रेनेंट होने की खबर बताकर चौंका दिया। महिला ने एक वीडियो में कहा कि दलती उन में प्रेग्नेसी में कुछ ज़ीखिम होते हैं, लेकिन डेफू का साथ होने के कारण यह डर भी खत्म हो गया है। शिन और डेफू की यह अनोखी प्रेम कहानी चाइनीज सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बहस का मुद्दा बन गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा रिश्ता है।

ठाकरे भाइयों ने अपने 'मिलन' के लिए महाराष्ट्र में समाज को भाषा के नाम पर बाँट दिया

नीरज कुमार दुबे

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर भाषा की भावनाओं की लहरों में डोलती दिखाई दे रही है। मराठी अस्मिता के सवाल को फिर से केंद्र में लाते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को कथित रूप से ‘थोपे जाने’ के विरोध में एक समान सुर अपनाया है। यह घटनाक्रम न केवल राज्य की भाषाई राजनीति को गर्मा गया है, बल्कि वर्षों से एक-दूसरे के विरोध में खड़े ठाकरे बंधुओं को साझा राजनीतिक उद्देश्य के तहत साथ भी ले आया है।
वैसे राज ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर से हिंदी भाषा का विरोध पहले भी होता रहा है। खासकर मुंबई जैसे महानगर में जहाँ हिंदी भाषी आबादी बड़ी संख्या में है, वहां मराठी भाषी समाज के मन में यह भाव डाला जा रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और भाषा को धीरे-धीरे हाशिये पर डाला जा रहा है। राज ठाकरे की मनसे ने पहले भी हिंदी भाषियों पर निशाना साधते हुए ऑटो रिक्षा चालकों और बहुभाषी दुकानों के खिलाफ अभियान चलाए हैं। वहीं शिवसेना की स्थापना ही ‘मराठी मानुष’ की राजनीति पर हुई थी, हालांकि बाद के वर्षों में वह राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधनों में आगे बढ़ती चली गई। दोनों भाई दो दशक के बाद एक ही मंच से जिस तरह गरजे हैं उससे हिंदी भाषियों के मन में सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है इसलिए, महाराष्ट्र सरकार की अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।
आज दोनों चचेरे भाइयों उद्धव और राज ने साथ आकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई शुरुआत भी कर दी है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक राजनीतिक परिवारों को बंटते देखा गया लेकिन ठाकरे बंधुओं ने एक साथ आकर जो पहल की है क्या उसका विस्तार पवार परिवार तक भी होता है, अब इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। आज की रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने अपने भाषण के जरिये वैसे तो कई बड़ी बातें कहीं लेकिन उन्हें हिम्मत करके कुछ जायज सवालों के जवाब भी देने चाहिए।
1. पहला सवाल यह है कि जिस हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा हासिल है उसके खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है? 2. दूसरा सवाल यह है कि हिंदी सिनेमा उद्योग ने जिस मुम्बई को विशिष्ट पहचान दिलाई और जो हिंदी सिनेमा उद्योग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की

ब्लॉग

सेकुलर और सोशलिस्ट को लेकर सियासी रार

उमेश चतुर्वेदी

इतिहास ने जब किसी कालखंड को काला अध्याय के रूप में स्वीकार कर लिया हो, तब उस कालखंड में लिए गए निर्णयों को वैधानिक कैसे माना जा सकता है। आपातकाल स्वाधीन भारत की तवारीख का काला दौर ही है। उसी दौर में संवैधानिक संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में ‘सेकुलर’ और ‘समाजवादी’ शब्द जोड़े गए। ऐसे में इन शब्दों को हटाने की मांग पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन हो रहा है विवाद। इसकी वजह यह है कि यह मांग खुलेतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। संघ की ऐसी आवाजें गैर बीजेपी दलों को अक्सर चुभती रही हैं। कांग्रेस ने इस बहाने संघ पर अपना पुराना आरोप दोहराना शुरू कर दिया, कि संघ और बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश में हैं। दिलचस्प यह है कि आपातकाल में कांग्रेसी अत्याचारों के शिकार हुए समाजवादी धड़े के दल भी संघ विरोध में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस बारे में क्या कहा है। आपातकाल की पचासवीं बरसी पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। ये शब्द पहले नहीं थे। बाद में इन्हें निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये शब्द संविधान में रहना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए।’ जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सत्ता में आई है, तभी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक रट लगाए हुए हैं कि बीजेपी और संघ संविधान बदलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उनकी अगुआई में समूचे विपक्ष ने इसे बार-बार दोहराया। नई लोकसभा के गठन के दौरान विपक्षी सांसदों ने शपथ लेते वक्त अपने हाथ में संविधान की प्रति थामे रखी। अंतर बस यह रहा कि कांग्रेसी सांसदों के हाथ में लाल रंग के कवर वाली संविधान की प्रति रही तो दूसरे दलों के सांसदों के हाथों में नीले रंग के कवर वाली संविधान की प्रति रही। शपथ लेते वक्त भी विपक्षी सांसदों ने देश को संदेश देने की कोशिश की कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और वे इसे बदलने नहीं देंगे। दत्तात्रेय होसबाले के बयान के बाद एक बार भी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल ऐसी ही बयानबाजी में मरसफ हो गए हैं।

संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। इसी के साथ लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पांच की बजाय छह साल कर दिया गया था। 1977 के आम चुनावों के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के जरिए आपातकाल के दौरान किए गए संवैधानिक बदलावों को बदल दिया। जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल को



रीढ़ की तरह है वहां हिंदी का विरोध करना क्या दोहरा रवैया नहीं है? फिल्मों को हिंदी बेल्ट से कमाई चाहिए लेकिन उसी हिंदी बेल्ट का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में हिंदी बोले तो क्या उसकी बेल्ट से पिटाई की जायेगी?

3. तीसरा सवाल यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तमाम अन्य मराठा वीरों ने तो अपने साम्राज्य का उत्तर और दक्षिण तक विस्तार किया था लेकिन उद्धव और राज मराठियों को संकुचित दायरे में ही क्यों रखना चाहते हैं?

हिंदी विरोध के बहाने साथ आये उद्धव और राज को समझना चाहिए कि हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन चुकी है। विदेशों में भी भारतीय, हिंदी को अपने मूल से जोड़ने वाली डोर मानते हैं। हिंदी पर मराठी भाषा की जीत का उत्सव मना रहे उद्धव और राज को समझना चाहिए कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन अंग है।

जन समर्थन खो चुके उद्धव और राज ठाकरे जैसे हिंदी विरोधियों को अपने मन की वह श्रांति दूर कर लेनी चाहिए कि हिंदी कोई विरोधी भाषा है, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदी तो एक सहयोगी भाषा है। यह कभी किसी पर थोपी नहीं जाती बल्कि अपनी उपयोगिता, पहुँच और आत्मीयता के बल पर यह जनमानस में रची-बसी है। हिंदी तो वह भाषा है जो भारत की भाषायी विविधता को बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं के साथ बड़ी आसानी से समन्वय कर लेती है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए साथ आये उद्धव और राज ठाकरे को समझना चाहिए कि



फिर से पांच साल करना शामिल था। लेकिन संविधान की प्रस्तावना से ‘सेकुलर’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने का प्रयास नहीं हुआ। संघ की मांग का आधार मूल संविधान की प्रस्तावना है। जिसमें ये दोनों शब्द शामिल नहीं किए गए थे। ऐसा नहीं कि ऐसा करने की मांग नहीं हुई थी। संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने 15 नवंबर 1948 को संविधान के मसौदे में संशोधन प्रस्ताव रखते हुए भारत की ‘धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समाजवादी राज्यों का संघ’ बनाने माँग की। लेकिन अंबेडकर ने इसे खारिज कर दिया। तब अंबेडकर ने कहा था, “राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए, ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों की समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं करना चाहिए।” अंबेडकर का मानना था कि अगर संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ दिया जाता है तो यह भावी पीढ़ियों को उनका रास्ता चुनने की स्वतंत्रता को सीमित करेगा। उन्होंने कहा, “इसे संविधान में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र की पूरी तरह से नष्ट कर देगा।” नेहरू की भी सोच थी कि भारतीय संविधान का चरित्र ही धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए उसकी प्रस्तावना में इसे अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस हो या फिर दूसरे विपक्षी दल, उन्हें आज के दौर में जब भी बीजेपी पर हमला या फिर संघ को कठघरे में खड़ा करना होता है, वे अंबेडकर के संविधान को याद करने लगते हैं। अंबेडकर के मूल्यों की रक्षा की बात करने लगते हैं। ऐसे में उनके सामने यह सवाल जरूर उठता है कि क्या आपातकाल थोपा जाना अंबेडकर के विचारों का सम्मान था और अगर वह नहीं था तो फिर सेकुलर और समाजवादी शब्दों का प्रस्तावना में शामिल होना सही कैसे है? एक और सवाल यह है कि जब आपातकाल ही नाजायज और अवैधानिक था तो

बनाने की कोशिश जरूर करेगी। बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ जरूर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तहत आक्रमक मुद्दा में नहीं है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी और संघ आपातकाल के लिए लगातार कांग्रेस से माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं। अगरजेडी प्रमुख लालू यादव भी आपातकाल के पीड़ित हैं और उन दिनों वे बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ थे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में ही उन्होंने छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था। ऐसे में उनके लिए आपातकाल के मुद्दे पर देर तक कांग्रेस का साथ देना आसान नहीं होगा। लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठाए और पीछे से उसका साथ वे देते रहें। इस रणनीति के जरिए उनकी कोशिश है कि बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन से सत्ता छीन लें। लेकिन संघ इस मांग से उस तरह पीछे हटता नहीं दिख रहा, जिस तरह 2015 के चुनावों के दौरान आरक्षण पर आए मोहन भागवत के बयान से उपजे विवाद के चलते पीछे हटता दिखा।

कांग्रेस ने अब तक आपातकाल को लेकर अपनी गलती नहीं मानी है। संघ की मांग के चलते यह मुद्दा उछल रहा है। जैसे-जैसे इस मुद्दे की तासीर बढ़ेगी, वैसे-वैसे कांग्रेस के लिए अपना बचाव कर पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि वह कैसे साबित कर पाएगी कि आपातकाल सही था? अगर वह आपातकाल को सही नहीं ठहरा पाएगी तो वह किस तरह साबित करेगी कि प्रस्तावना में किया गया बदलाव सही था। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है। चूँकि संघ के पास सीधे तौर पर कोई वैधानिक ताकत नहीं है। लेकिन विमर्श के बहाने वह इन शब्दों के औचित्य के साथ ही कांग्रेस की तब की करतूत की याद को जीवंत बनाए रखना चाहता है। इसके जरिए निश्चित तौर पर एक ऐसा लोकमानस बनेगा, जो इन शब्दों का विरोधी होगा।



16 करोड़ की प्रॉपर्टी, 18 लोगों का गैंग, अवैध धर्मांतरण मामले में अरेस्ट छांगुर के खाड़ी देशों से जुड़े तार

आर्यावर्त संवाददाता

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और अवैध धर्मांतरण के मामले में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेतृत्व वाले 18 सदस्यीय गैंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) की जांच में सामने आया है कि छांगुर ने न केवल तहसील और न्यायालयों में गहरी पैठ बनाई थी, बल्कि पुणे में 16 करोड़ रुपये की संपत्ति का सौदा भी किया, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के लिपिक की पत्नी को हिस्सेदार बनाया गया। इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें अब तक चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 14 अन्य की तलाश जारी है।

एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर ने उतरौला तहसील के कर्मचारियों से सांठागंठ कर एक तालाब को अपने नाम करवा लिया था।

टनकपुर हाईवे के किनारे बसाई जा रही कॉलोनी का विवाद गरमाया, मंदिर का रास्ता बंद करने के विरोध में हाईवे जाम

आर्यावर्त संवाददाता

पीलीभीत। शहर में टनकपुर हाईवे किनारे विकसित की जा रही एट्टू जेड डायमंड कालोनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अब नया मामला प्राचीन बाबा नागेश्वरधाम धाम मंदिर का रास्ता बंद करने का सामने आया है। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ हाईवे जाम कर दिया। इसके चलते वहां लगभग दो घंटे तक हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह प्रदर्शनकारियों को शांत किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कालोनी विकसित कर रहे एट्टू जेड ईएम प्रग्राइवेट लिमिटेड के स्वामी ने प्राचीन बाबा नागेश्वरधाम मंदिर के मुख्य मार्ग को ट्रांसफार्मर रखकर बंद कर दिया है। जिस कारण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिर को नुकसान

फंदे पर लटकी मिली छात्रा की लाश, हथेली पर था सैड वाला इमोजी, लिखा था– आई मिस यू गुलशन

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आत्महत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके में एक 12वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसकी मां उसे खाना खाने के लिए बुलाने गईं तो उसको फंदे से लटका पाया। अपनी बेटी को लटके देख मां चीख पड़ी। आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

ये घटना शनिवार की है। खुदकुशी करने वाली 12वीं की छात्रा मिर्लकबोर्ड चौकी इलाके में रहने वाले किराना दुकानदार की बेटी थी। मृतक छात्रा 18 साल की थी। पुलिस को छात्रा द्वारा शनिवार रात लगभग 10 बजे आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस



इसके अलावा, उसने पुणे के मावल तहसील के कुनेनामा गांव में 16 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी और इसका व्यावसायिक एग्रीमेंट तैयार किया। इस सौदे में बलरामपुर के बड़ा घुसाह गांव की संगीता देवी को हिस्सेदार बनाया गया, जो सीजेएम कोर्ट के लिपिक राजेश उपाध्याय की पत्नी हैं।

एटीएस की रिपोर्ट के अनुसार,

संगीता को जमीन के कारोबार से होने वाले मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया था। छांगुर ने न्यायालय में अपनी पहुंच का दुरुपयोग करते हुए उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जो उसके धर्मांतरण के एजेंडे का विरोध करते थे। एटीएस ने खुलासा किया कि संचित और मालती देवी, जो अनुसूचित वर्ग से हैं, ने इस्त्मा धर्म

अपनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छांगुर के गैंग ने कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।

18 सदस्यीय गैंग, 14 की तलाश

एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, छांगुर का गैंग 18 लोगों का था, जिसमें

होटल के पीछे मिली अज्ञात युवती की लाश, हड़कम्प

बाराबंकी। कोतवाली नगर क्षेत्र के बड़ेल फतहाबाद में एक निजी होटल के पीछे की तरफ एक अज्ञात युवती उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव सोमवार को संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची बड़ेल चौकी की पुलिस ने मिले शव की शिनाख्त की तमाम कोशिशें की लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर सका जिसके बाद अगले 72 घंटों के लिए बरामद शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम गृह में सुरक्षित रखवाया गया है,चौकी ईंचार्ज रवीन्द्र कुमार सिंह ने बताया की बरामद शव की पहचान नहीं हो पाई है शव अगले 72 घंटों के लिए पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया शरीर में कोई चोट अथवा कोई ऐसी संदेहास्पद नहीं है इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।दिन भर उस जगह पर लोगों का आवागमन बना रहता है और अचानक वहां पर अज्ञात युवती का शव मिला संदेह पैदा करता है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे जैसे जिलों के लोग शामिल थे। यह गैंग संगठित तरीके से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था और देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। शनिवार को छांगुर और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी के बाद गैंग के बाकी 14 सदस्य भूमिगत हो गए हैं। एटीएस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही।

जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मूल रूप से गैड्रास बुजुर्ग के रेहरा माफ़ी गांव का रहने वाला है। वर्तमान में वह उतरौला के मधपुर में आलीशान कोठी में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं

उतरौला के प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि छांगुर और नीतू की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में

इंजीनियर बहू ने सास को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा, ससुर बोले– पिता दरोगा हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई

आर्यावर्त संवाददाता

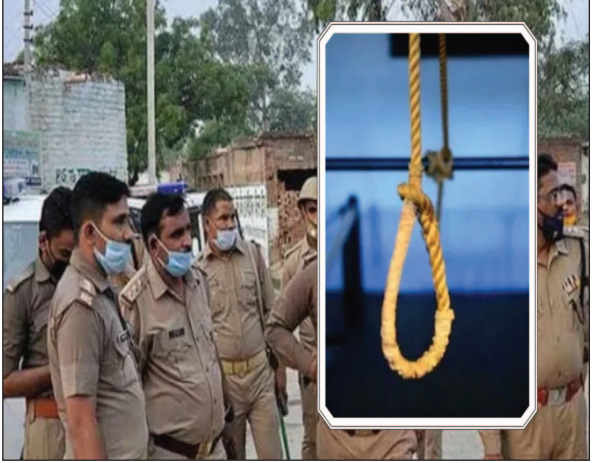
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने अपनी सास को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। ये घटना गाजियाबाद के गोविंदपुरम थाना इलाके की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सास की बेरहमी से पिटाई करने वाली आरोपी बहू का नाम आकांक्षा है।

पीड़ित सास ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी अपनी बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बहू के पिता दिल्ली में दारोगा हैं, इसलिए पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी बहू अकांक्षा दिल्ली की रहने वाली हैं। उसकी शादी गाजियाबाद के गोविंदपुरम थाना इलाके में हुई है। बहू द्वारा सास की पिटाई की ये घटना

एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, दिए निर्देश

सिरौलीगौसपुर बाराबंकी। उपजिलाधिकारी प्रीति सिंह ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोठारी गौिया और सुबेदारपुरवा गांवों में हो रही हल्की कटाई की स्थिति का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर है। हालांकि अभी यह खतरे के निशान से नीचे है और नदी का पानी अपनी सीमा में बह रहा है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता एसके सिंह के अनुसार क्षेत्र में हो रही हल्की कटान को रोकने के लिए अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाढ़ राहत केंद्र सनावा में नायब तहसीलदार अन्नू सिंह की अध्यक्षता में बाढ़ चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी दी। नायब तहसीलदार ने बताया कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में लोगों को ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। प्रशासन ने छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

17 साल, एक परिवार और 10 सुसाइड...बीते 21 दिन में चाचा-भतीजे ने दे दी जान



10 बजे खाना खाने के बाद खेतों की ओर यह कहते हुए गया था कि जामुन खाने जा रहा हूं। साथ ही उसने कहा कि धूप ज्यादा है तो बहन का दुपट्टा ले जा रहा हूं।

जब वह काफी देर से वापस वह

धर्मांतरण कांड में घिरे छांगुर पीर की संपत्तियों पर सरकार की कड़ी नजर, ब्योरा खंगालने में जुटा प्रशासन

आर्यावर्त संवाददाता

बलरामपुर। उतरौला के बहुचर्चित धर्मांतरण कांड में गिरफ्तार स्वयंभू पीर छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने अब आरोपी की संपत्तियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शासन स्तर से राजस्व विभाग को निर्देश मिला है कि छांगुर बाबा की सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराया जाए — चाहे वह नगर क्षेत्र में हो या देहात में, उनके नाम से हो या रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत हो। सूत्रों के मुताबिक, उतरौला तहसील प्रशासन को शासन से स्पष्ट निर्देश मिला है कि आरोपी की पूरी संपत्ति की जानकारी इकट्ठा की जाए ताकि वैधानिक रूप से जब्तीकरण अथवा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। राजस्व विभाग के अधिकारियों

की टीमें अब ग्राम स्तरीय अभिलेख, नगर निकाय संपत्ति रजिस्टर और भूलेख प्रणाली से जुड़ी जानकारी खंगाल रही हैं।

बताया जा रहा है कि छांगुर पीर ने पिछले कुछ वर्षों में उतरौला कस्बे और आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है, जिनमें से कई संदेहास्पद तरीके से खरीदी गई हैं। एटीएस की जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विदेशों से अवैध फंडिंग के जरिए इस नेटवर्क को संचालित किया जा रहा था। इसी कड़ी में इन संपत्तियों को काले धन का ठिकाना भी माना जा रहा है। जनपद प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मांतरण जैसे राष्ट्रविरोधी अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि संपत्तियों को खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी पाई गई।



एक जुलाई की बताई जा रही है।

सास को दौड़ा-दौड़ाकर मारा

जानकारी के अनुसार, एक जुलाई को आरोपी बहू आकांक्षा अपनी मां के साथ ससुराल पहुंची

और अपनी सास सुदेश देवी को पिटाई की। इस घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें आरोपी बहू और उसकी मां को सास को दौड़ा-दौड़ाकर मारते देखा जा सकता है। सास खुद को बचाने का प्रयास करते भी देखी

भतीजे को देखकर आपे से बाहर हुई चाची, चाकू उठाकर कई बार घोंपा... दहला देगा ये हत्याकांड

आर्यावर्त संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के भुता थाना क्षेत्र के गांव म्यूड़ी कला में जमीन को लेकर हुए झगड़े ने एक युवक की जान ले ली। इस सनसनीखेज वारदात में चाची ने अपने प्रेमी और पति के साथ मिलकर भतीजे की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला, उसके पति और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गांव में शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे शुरू हुआ जब जमीन पर दीवार बनाने को लेकर विवाद हुआ।

गांव निवासी चरन सिंह की पत्नी और उनके भतीजे उमाकांत की पत्नी कान्ति देवी के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर यह मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोपी महिला ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पत्नी और चाची के बीच बहस हो रही थी भती उमाकांत

वहां आ गया और अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए चाची से बहस करने लगा। तभी गुस्से में आकर चाची ने अपने पास रखे चाकू से उमाकांत पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसके पैट और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू लगे। इतना ही नहीं वहां मौजूद आरोपी महिला का करीबी और कथित तौर पर प्रेमी गौरव भी पीछे नहीं रहा। उसने भी उमाकांत को चाकू मारे। पत्नी कान्ति देवी के सामने ही उसका पति लहलुहान होकर गिर पड़ा। शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह खून से लथपथ उमाकांत को सीएचसी कुंआडांडा पहुंचाया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उमाकांत को मृत घोषित कर दिया।

दबंगई, अवैध संबंध और बेदखली की कहानी

जांच में सामने आया कि आरोपी महिला गांव में काफी दबंग किस्म की

महिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि महिला के गौरव नाम के युवक से अवैध संबंध हैं। यही बात अनीता के परिवार वालों को भी पसंद नहीं थी। ग्रामीणों के मुताबिक चरन सिंह के पिता लीलाधर ने अपनी बहू (आरोपी महिला) के चरित्र पर सवाल उठाते हुए बेटे चरन सिंह और बहू दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इसके बाद से ही जमीन के बंटवारे और दीवार बनाने को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था। इसी विवाद ने धीरे-धीरे इतना तूल पकड़ लिया कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी गौरव और पति चरन सिंह के साथ मिलकर भतीजे उमाकांत को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल महिला, उसके पति चरन सिंह और प्रेमी गौरव को घटना के 10 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया।

अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और आपको भी 20वीं किस्त का इंतजार है, तो जान लें कि अब चर्चा 18 जुलाई की हो रही है। माना जा रहा है कि 20वीं किस्त इस दिन जारी हो सकती है।

दबाव और विरोध के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐलान किया है कि देश में आम चुनाव दिसंबर से जून 2026 तक करा दिए जाएंगे। यूनस लंबे समय से चुनावों को टाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वादा किया है कि वह जून 2026 से आगे किसी नहीं संभालेंगे।

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

10 जुलाई को याचिकाओं पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वह निर्वाचन आयोग के इस कदम की वैधता पर निधारित लिथि को विचार करेगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस (पीडब्ल्यूडी) पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कई याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार (10 जुलाई) को मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई। सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि वह इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करे। इस पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, हम इस मामले को गुरुवार को सुनेंगे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजद सांसद मनोज झा, एडीआर और टीएमसी



सांसद महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग की है, जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। राजद का कहना है कि विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है।

मनोज झा ने कहा कि निर्वाचन आयोग का 24 जून का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का

(एसआईआर) किया जा रहा है। महुआ ने अपनी याचिका में कहा, अगर इस आदेश को रह नहीं किया गया, तो यह देश में बड़े पैमाने पर पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है, जिससे लोकतंत्र, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कमजोर हो सकते हैं। महुआ ने शीर्ष अदालत से भारत निर्वाचन आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण के इस तरह के आदेश जारी करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' भी एक याचिका दायर कर चुका है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज रक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं, वे पहले ऐसे नहीं थे। आज के बदलाव गतिशील और अनिश्चित हैं। शांति का समय एक धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि हम सभी को शांति के समय में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अचानक हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो हमें जगाती

है और हमें कुछ और करने की आवश्यकता का अहसास होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी उपकरण की अचानक आवश्यकता बढ़ जाती है, तो हम सभी को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। यह सब शांति के समय में करने की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हम सभी को रक्षा अर्थशास्त्र में एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि पूरा विश्व पुनः शस्त्रीकरण के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में कई पूंजी निवेश किए जा रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने नियंत्रक सम्मेलन आयोजित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका दिमाग खुला और ग्रहणशील होना चाहिए। रक्षा लेखा विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब-किताब रखना नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसका असर हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों तक भी पहुंचता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे एक सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ रहेगा।

हमारा रक्षा बजट बहुत बड़ा

राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर

आप हमारे रक्षा बजट को देखें तो यह दुनिया के कुछ देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। जब लोगों की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया जाता है तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। हमें प्रभावी विकास की आवश्यकता है। हमारा रक्षा व्यय ऐसा होना चाहिए कि न केवल बजट बड़े, बल्कि हम इसका सही तरीके से उपयोग भी कर सकें। सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उचित तैनाती करके। उन्होंने कहा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहली बार जैम पोर्टल से पूंजी खरीद की अनुमति दी है, यह एक सराहनीय कदम है। मुझे यह भी बताया गया है कि विभाग रक्षा कर्मियों के लिए व्यापक वेतन प्रणाली और केंद्रीकृत डाटाबेस प्रबंधन पर काम कर रहा है।

रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) सात से नौ जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) एसजी दस्तोदार और रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉ मयंक शर्मा शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन नीतिगत संवाद, रणनीतिक समीक्षा और संस्थागत नवाचार का

एक प्रमुख मंच है। यह रक्षा और वित्त क्षेत्रों में रक्षा लेखा विभाग के शीर्षस्थ नेतृत्व, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और हितधारकों को एक साथ लाता है।

वया है सम्मेलन का उद्देश्य, समझिए

वहीं बात अगर इस सम्मेलन के उद्देश्य की करें तो यह सम्मेलन रक्षा और वित्त क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, थिंक टैंकों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाकर रक्षा वित्तीय प्रणाली की समीक्षा, सुधार और भविष्य की दिशा तय करने का काम करता है। वहीं इस बार का विषय वित्तीय सलाह, भुगतान, ऑडिट और रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के जरिए लेखांकन में बदलाव है। बता दें कि यह डीएडी को पारंपरिक अकाउंटिंग विभाग से बदलकर आधुनिक और रणनीतिक रक्षा वित्त संस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अब बात अगर इस सम्मेलन में मुख्य बिंदु की करें तो सम्मेलन में आठ उच्चस्तरीय सत्र (मंथन सत्र) होंगे, जिनमें बजट सुधार, आंतरिक ऑडिट में बदलाव, मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग), संयुक्त शोध, और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

ट्रोलर्स पर भड़कीं उफ़ीं जावेद, बोलीं नफरत नहीं रोक पाएंगी



करण जौहर का शो द ट्रेटर्स जीतने के बाद, उफ़ीं जावेद ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बताया है कि कैसे उन्हें कुछ लोगों से धमकियां और अपमानजनक मैसेज मिल रहे हैं।

उफ़ीं ने इंस्टाग्राम पर ट्रोलर्स के मैसेज के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करते हुए लिखा, जब आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती, तो बस आप उसके लिए आर शब्द छोड़ देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब मुझे इस तरह से धमकियां या गाली मिल रही है, लेकिन इस बार यह मेरे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि मेरे शो जीतने की वजह से हो रहा है। जब आपको मनपसंद खिलाड़ी नहीं जीतता, तो आप गाली देने लगते हो। ये मेरे अपलोड किए गए अच्छे वीडियो हैं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लोगों को बस नफरत फैलाना और गाली देना पसंद है। अगर हर्ष को शो से न निकालती तो प्यार में अंधी, हर्ष को निकाल दिया तो धोखेबाज। पूरव को जीतने देती तो बेवकूफ, जीतने नहीं दिया तो धोखेबाज। नफरत ने मुझे पहले कभी नहीं रोका और न अब रोक पाएंगी।

उफ़ीं जावेद को उनके बोल्लड और रिवीलिंग आउटफिट्स को लेकर हमेशा ट्रोलिंग का सामना

राजकुमार राव अभिनीत फिल्म मालिक के निर्माताओं ने इसका टाइटल ट्रैक राज करेगा मालिक रिलीज कर दिया गया है। मालिक 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक राज करेगा मालिक रिलीज कर दिया है। इस गाने में राजकुमार का स्वैग और मानुषी का जबरदस्त डांस फैस को बेहद पसंद आ रहा है। तो वहीं कुछ यूजर्स मालिक के गाने राज करेगा मालिक को शाहिद कपूर की विवाह के एक गाने से कंपेयर कर रहे हैं।

टाइटल ट्रैक बीट्स और वीरता का एक जोशीला मिश्रण है, जिसे गतिशील जोड़ी सचिन-जिगर ने संगीतबद्ध किया है, जिसे अकासा ने आवाज दी है और एमसी स्क्वायर ने धमाकेदार रैप दिया है, तथा इसे महान अभिमात्र भट्टाचार्य ने लिखा है। अपनी

धड़कती लय और विद्रोही भावना के साथ, यह गाना प्लेलिस्ट पर छा जाने और फिल्म की उच्च-दांव वाली दुनिया के लिए टोन सेट करने के लिए तैयार है।

मालिक, एक आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन डायरेक्टर पुलकित ने किया है। राजकुमार राव फिल्म में लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। इसमें राजकुमार के अपोजिट मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। इस एक्शन-थ्रिलर में राजकुमार एक गैंगस्टर की भूमिका निभाएंगे, जो उनकी पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। मालिक का निर्माण टिप्स फिल्मस और नॉर्दन लाइट्स फिल्मस ने किया है। यह फिल्म 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।



आमिर खान की साउथ सिनेमा में धमाकेदार एंट्री, फर्स्ट लुक से मची सनसनी, रजनीकांत की फिल्म कूली में उड़ाएंगे गर्दा

सितारे जमीन पर के बाद, आमिर खान रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म कूली में कैमियो करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार अपनी तमिल डेब्यू फिल्म में दाहा का किरदार निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेकर्स ने फिल्म से उनका पहला लुक रिलीज कर दिया है और इंटरनेट पर लोग इसे देखकर हैरान रह गए।

आमिर खान का ब्लैक बनियान पहने, स्टाइलिश स्वैग से सिगार पीते हुए, थांलू लुक इंटरनेट पर छाया हुआ है। यह किरदार उनके हाल के वर्षों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से बिल्कुल अलग लुक है। एक्स पर पोस्ट की गई एक मोनोक्रोम तस्वीर में उनका साइड प्रोफाइल लुक जिसमें वे चश्मा पहने हुए हैं, शेरर किया गया है। इसके साथ मेकर्स ने कैप्शन लिखा, कूली की दुनिया से आमिर खान को दाहा के रूप में पेश करते हुए कूली 14 अगस्त से दुनिया भर के आईमैक्स स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार है।

कूली से सामने आए आमिर के इस लुक ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। दर्शकों को आमिर का यह लुक खूब पसंद आ रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया, आमिर का यह मास अवतार वाकई कमाल का है। एक ने लिखा, क्या स्वैग है। एक ने कमेंट किया, क्या एटीट्यूड और



वाली है। हाल ही में आमिर ने रजनीकांत में अपने होने की पुष्टि की थी, उन्होंने बताया था कि वह

इस फिल्म को करने के लिए इसलिए माने क्योंकि वे रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं। कूली में उनके कैमियो के बारे में एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए आमिर खान ने कहा, मुझे यह करने में बहुत मजा आया। मैं रजनी सर का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे मन में रजनी सर के लिए बहुत प्यार और सम्मान है। इसलिए, मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी। जब लोकेश ने मुझे बताया कि यह रजनी सर की फिल्म है और वह चाहते हैं कि मैं इसमें कैमियो करूं, तो मैंने कहा, ठीक है, मैं इसे कर रहा हूं, जो भी हो, मैं इसे कर रहा हूं।

इस बीच आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के तीन साल बाद सितारे जमीन पर के साथ फिल्मों में लौटे, इस फिल्म में उनके साथ जेनेलिया देशमुख और 10 ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने पहली बार बड़ी स्क्रीन पर परफॉर्मेंस दी।

कूली एक तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे लोकेश कनगराज ने निर्देशित और सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। रजनीकांत फिल्म में लीड रोल में हैं, उनके साथ सौविन शाहिर, नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज और उपेंद्र अहम रोल में हैं। कूली को 2025 में दुनिया भर में वर्ल्डवाइड और आईमैक्स में रिलीज किया जाएगा।

